दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि 1-1-1989 से 28-2-1989 की अवधि के दौरान 18 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें उचित दर दुकानदारों पर कम तोलने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली प्रशासन द्वारा ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है तथा दोषी पाए गए उचित दर-दुकानदारों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

(ख) और (ग) एक उचित दर-दुकान, दुकान सं० 3, नार्थ एवेन्यू में चल रही है। उचित दर-दुकान इलाके के लोगों की सुविधा के लिए दुकान के एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल सब्जी बेचने के लिए कर रहा है। दिल्ली प्रशासन ने आगे बताया है कि विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं के भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तथा उन्हें तोलने के लिए उपयुक्त व्यवस्था मौजूद है।

संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर

2606. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में संसद सदस्यों से प्राप्त कितने पत्र 3 महीने, 3-6 महीने, 6-9 महीने, 9-12 महीने और एक वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) इनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं तथा इन पत्रों के शीघ्र उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उर्वरक डीलरशिप

2607. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में जिलावार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कितनी-कितनी उर्वरक डीलरशिप दी गयी ; और

(ख) सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार का कितना कोटा निश्चित किया है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी गयी थी कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए 25 प्रतिशत की उर्वरक डीलरशिप का आरक्षण किया जाए।

Number of factories closed during 1988-89

2608. SHRI PRITHIBI MAJHI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of factories closed, state-wise during 1988-89 till date; and

(b) the number of mandays lost during the above period?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) Based on the latest available information, a statement giving state-wise number of industrial units closed during 1988 is attached. (*See* below).

(b) The number of mandays lost due to strikes and lockouts was 29.30 million during January—November, 1988.